

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 1973/अग्रहायण 3, 1895

No. 283] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24, 1973/AGRAHAYANA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रतिलिपि संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th November 1973

SUBJECT :—Exports to the Arab Republic of Egypt and Sudan under Indo-ARE and Indo-Sudan Trade Arrangements.

No. 38-ETC(PN)/73.—It is notified for the information of all exporters that the Indo-ARE Trade Arrangement for the period 1st October 1973 to 30th September 1974 has been concluded and Indo-Sudan Trade Arrangement has been extended upto 31st August 1974.

2. Attention of all exporters is invited to Public Notices No. 9(ETC)/PN/71 dated the 17th November 1971, No. 18-ETC(PN)/72 dated the 8th September 1972 and No. 7-ETC(PN)/73 dated the 13th March 1973, wherein procedure for centralised confirmation of letters of Credit for exports to the Arab Republic of Egypt and registration of contracts for exports to Sudan has been laid down. These instructions are recapitulated for compliance by all exporters:

- (1) All exports to Arab Republic of Egypt under the Indo-ARE Trade Arrangement should be made only against valid letters of Credit reconfirmed by the State Bank of India, Bombay. It should be noted that this reconfirmation of letters of credit by the State Bank of India, is to be in addition to the normal confirmation to be given by the bank on which the credit is opened.
- (2) No shipments to Sudan would be allowed under the Indo-Sudan Trade Arrangement unless the contract is first registered with the State Bank of India, Bombay. The State Bank of India, Bombay will register such contracts on payment of service charges fixed by the Bank. Exporters can have their documents forwarded to State Bank of India, Bombay through any branch of any bank. On registration, the State Bank of India, Bombay will issue to the exporters a certificate which will entitle the letter to effect shipments. Without this certificate no shipments to Sudan would be allowed.

- (3) Before shipping goods to Sudan against contracts registered with the State Bank of India, Bombay, exporters should ensure that the Sudanese importers possess valid import licences duly franked by the Bank of Sudan.
- (4) As and when shipments are effected to ARE/Sudan against the contracts registered with State Bank of India, Bombay, the value of the shipment and the balance value of the contract should be intimated to the State Bank of India, Bombay, quoting their registration number and the particulars of the Credit concerned.
- (5) It may be noted that under current Indo-ARE and Indo-Sudan Trade Arrangements there is no provision for new deferred payments contracts. Therefore no new contracts should be entered into for exports to these countries on deferred payments basis.

K. S. NARANG, Jr. Secy."

वाणिज्य सञ्चय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1973

विषय:—भारत-मिस्र अरब गणतन्त्र और भारत सूडान व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मिस्र और अरब गणतन्त्र और सूडान को निर्यात ।

संख्या 38 आई०टी०सी० (पी०एन०)/73. —सभी निर्यातकों को जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 1 अक्टूबर 1973 से 30 सितम्बर, 1974 तक की अवधि के लिए भारत-मिस्र अरब गणतन्त्र व्यापार व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है और भारत-सूडान व्यापार व्यवस्थाओं को 31 अगस्त 1974 तक बढ़ा दिया गया है ।

2. सभी निर्यातकों का ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 9 (ई टी सी)/पी एन/71 दिनांक 17 नवम्बर 1971, सं० 18—ई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 8 सितम्बर 1972 तथा सं० 7—ई० टी० सी (पी एन)/73 दिनांक 13 मार्च 1973 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिनमें मिस्र के अरब गणतन्त्र का निर्यातों के लिए साख पत्र के केन्द्रीय पुष्टिकरण के लिए और सूडान को निर्यातकों के लिए संविदाओं के पंजीकरण के लिए क्रियाविधि निर्धारित की गई है। इन अनुवेशों को सभी निर्यातकों द्वारा अनुपालन करने के लिए संसद में पुनः उद्धृत किया जाता है—

(1) भारत-मिस्र अरब गणतन्त्र व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत मिस्र अरब गणतन्त्र को सभी निर्यात, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई द्वारा पुनः पुष्टीकृत वध साख पत्रों के मद्दे ही किए जाने चाहिए। इसे नोट कर लेना चाहिए कि स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा साख-पत्रों का यह पुनः पुष्टीकरण, उस बक द्वारा दिए जाने वाले सामान्य पुष्टिकरण के अलावा होगा जिसमें साख पत्र खोला जाता है ।

(2) भारत-सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत सूडान के लिए तब तक किसी क्रिम के पोतलदान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी जब तक कि संविदा स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई में पहले ही पंजीकृत नहीं करवा ली जाती है। स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई ऐसी संविदाओं को उनके द्वारा निश्चित सेवा प्रभार चुकान पर ही पंजीकृत करेगा। निर्यातक अपने दस्तावेजों को बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई को अग्रेसित करा सकते हैं। पंजीकरण करव पर,

स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई निर्यातकों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जो निर्यातकों को पोतलदान प्रभावी करने के लिए पात्र बनाएगा : इस प्रमाण पत्र के बिना सूडान के लिए किसी भी पोतलदान की सस्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

- (3) स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई में पंजीकृत की गई संविदाओं के आधार पर सूडान का माल के पोतलदान करने से पहले निर्यातकों को इस बात का भली भांति मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सूडान के आयातक, सूडान के बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित वैद्य आयात लाइसेंसों के धारक हैं ।
- (4) स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई में पंजीकृत की गई संविदाओं के आधार पर मिस्र अरब गणतन्त्रःसूडान के लिए पोतलदान जब और जैसे ही प्रभावी कर लिए जाएं स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई को उनके पंजीकरण संख्या और सम्बद्ध साख के व्योरो का हवाला देते हुए पोतलदान के मूल्य और संविदा में शेष मूल्य के बारे में सूचना देनी चाहिए ।
- (5) इसे मोट कर लिया जाए कि वर्तमान भारत-मिस्र अरब गणतन्त्र तथा भारत-सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत नई आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है । इसलिए इन देशों को निर्यात करने के लिए आस्थगित भुगतानों के आधार पर नई संविदाएं नहीं की जानी चाहिए ।

के० एस० नारंग, संयुक्त सचिव ।

